मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बैगा, गुनिया, सिरहा को दी सम्मान निधि की सौगात

- जनजातीय गांवों में धार्मिक व मांगलिक कार्य के लिए अखरा निर्माण विकास की योजना होगी शुरू
- जनजातीय समुदाय के शहीदों की चिन्हित स्थलों पर लगेंगी प्रतिमाएं
- जनजातीय विद्रोह के शहीदों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन हुए सम्मानित

रायपुर। आरएनएस

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने साइंस कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि जनजातीय समाज का इतिहास बहुत समृद्ध और गौरवशाली है। पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनजातीय समुदाय के मान, सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम किया है। अटल जी ने जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए पृथक से मंत्रालय बनाया और इस समुदाय के विकास को एक नई दिशा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 24,000 करोड़ रूपए और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 80,000 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया है, जिसके चलते जनजातीय इलाकों में तेजी से बुनियादी सुविधाओं का विकास और जनजातियों की बेहतरी के काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150 वीं जयंती वर्ष समारोह के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातीय समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बैगा, गुनिया, सिरहा लोगों के लिए मुख्यमंत्री सम्मान निधि दिए जाने की घोषणा की। इसके तहत उन्हें प्रति वर्ष 5 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनजातीय गांवों में धार्मिक एवं मांगलिक कार्य के लिए अखरा निर्माण विकास योजना शुरू करने और जनजातीय समुदाय के शहीदों की प्रतिमाएं चिन्हित स्थलों पर स्थापित किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री साय ने समारोह में जनजातीय समुदाय के विभूतियों, राज्य में हुए जनजातीय विद्रोह के शहीदों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने जनजातीय चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर वन अधिकार अधिनियम से संबंधित ''एटलस'', कैलेण्डर ''शौर्यांजलि'' तथा ''हल्बा जनजातीय की वाचिक परंपराएं'' विषय पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया। इनका प्रकाशन छत्तीसगढ़ आदिम जाति विकास विभाग द्वारा किया गया है। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राज्यसभा सांसद अरूण सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में सभी वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की लोकप्रियता और विनम्रता की सराहना पूरे देश में होती है। उन्होंने कहा कि रायपुर में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस एवं अंतर्राज्यीय नृत्य महोत्सव समारोह में आकर ''एक भारत-श्रेष्ठ भारत'' का दर्शन हुआ है। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के इस विशेष आयोजन के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को बधाई दी। उन्होंने इस मौके पर जनजातीय समुदाय के महापुरूषों को नमन करते हुए कहा कि वही देश और समाज जागृत रहता है, जो अपनी संस्कृति और अपने महापुरूषों को याद रखता है।

आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए चिंता की है। उन्होंने इस समुदाय के विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से छत्तीसगढ़ के साढे छह हजार गांवों और ग्रामीणों का समग्र विकास होगा। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय समुदाय के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित दो दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम, राज्यसभा सांसद अरूण सिंह, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में उपस्थित जनसमुदाय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सम्बोधन को न सिर्फ सुना, बल्कि वर्चुअल रूप से उसका हिस्सा भी बना। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर देश के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी सुविधाओं के विकास एवं विस्तार वाली 6600 करोड़ की लागत वाली कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने देश के जनजातीय इलाकों और जनजाति समुदाय के कल्याण के लिए पांच गुना बजट खर्च कर रहे हैं। दस साल पहले इसका बजट मात्र 25,000 करोड़ रूपए हुआ करता था, जो अब बढक़र 1,25,000 करोड़ रूपए हो गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज बिहार के जमुई में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150 वीं जयंती वर्ष के शुभारंभ समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। जमुई में आयोजित इस कार्यक्रम का लाईव प्रसारण पूरे देश में हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमने इतिहास के एक बहुत बड़े अन्याय को दूर करने का एक ईमानदार प्रयास किया है।

महत्वपूर्ण एवं खास

माओवादियों के साथ मुठभेड़: उत्तर अबूझमाड़ क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्यवाई जारी

नारायणपुर/कांकेर (आरएनएस)। उत्तर अबूझमाड़ क्षेत्र में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्चिंग अभियान के दौरान, आज सुबह 8 बजे से लगातार डीआरजी (जिला रिजर्व गार्ड), एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) और बीएसएफ (बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स) की संयुक्त पुलिस पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बता दें कि माओवादियों के छुपे होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने उत्तर अबूझमाड़ क्षेत्र में सर्चिंग अभियान शुरू किया था। अभियान के दौरान, माओवादियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच रुक-रुक कर गोलीबारी हो रही है। फिलहाल, मुठभेड़ जारी है और सुरक्षा बलों द्वारा पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की जा रही है। पुलिस और माओवादियों के बीच गोलीबारी का सिलसिला जारी है, और सर्च अभियान को बिना रुके जारी रखा जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में सर्द हवाओं से बढ़ी ठिठुरन

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। लगभग सभी हिस्सों में हल्की ठंड तो कहीं कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। लोग अपने आप को ठंड़ी हवाओं से बचाने के लिए अलाव का सहारा लेने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में आसमान साफ होते ही सर्दी का असर बढऩे लगा है। वर्तमान में रायपुर समेत सभी जिलों में दिन और रात के पारा में गिरावट होने से ठिठुरन बढ़ रही है। दरअसल, द्रोणिका के प्रभाव के कारण हवा में नमी की मात्रा घट रही है, जिसके बाद तापमान में गिरावट हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से दिनों के भीतर तापमान में 5 से 6 डिग्री गिरावट के आसार है। बता दें कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में जल्द ही बर्फबारी शुरू होगी। इसका सीधा असर छत्तीसगढ़ के तापमान पर पड़ेगा, जिससे दिन और रात दोनों समय ठंड बढऩे की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि, दिसंबर से ही तेज सर्दी की शुरूआत होगी। वहीं नवंबर के दूसरे व चौथे सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हल्की बारिश हो सकती है।

पैसा लगाने का झांसा देकर 7 लाख से अधिक की ठगी

रायपुर (आरएनएस)। अज्ञात आरोपी ने स्टाक मार्केट में पैसा लगाने का झांसा देकर युवक से 7 लाख 84 हजार 33 रुपए की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर राखी पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी दीपक कुमार निषाद 33 वर्ष सेक्टर 27 नवा रायपुर का रहने वाला है। प्रार्थी ने राखी थाना में शिकायत किया कि अज्ञात मोबाइल क्रमांक 87795-18002 के धारक ने प्रार्थी को फोन कर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का झांसा देकर अपने बताएं खाते में 7 लाख 84 हजार 33 रुपए अपने खाते में जमा करवा लिया। जब प्रार्थी को ठगे जाने का अहसास हुआ तो उसने इसकी शिकायत राखी थाना में की। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

पूर्व सीएम भूपेश के खिलाफ विधायक रिकेश सेन ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

दुर्ग-रायपुर। आरएनएस

जिले की वैशाली नगर सीट से भारतीय जनता पार्टी विधायक रिकेश सेन ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक भूपेश बघेल के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। रिकेश सेन ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल लगातार अनर्गल ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की साय सरकार को बदनाम कर रहे हैं। विधायक सेन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने हाल ही में अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट में यह टिप्पणी की थी कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार में स्कूल बंद और स्कॉच शुरू है। इस बयान को लेकर रिकेश सेन ने पूछा कि 'कौन सा स्कूल बंद हुआ है', उन्होंने कहा कि यह पूर्व सीएम का यह आरोप पूरी तरह से आधारहीन और भ्रामक है। बता दें कि विधायक सेन ने सुपेला थाना प्रभारी राजेश मिश्रा को शिकायत पत्र सौंपा और दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला के नाम भी शिकायत दी है। उन्होंने आगे कहा कि यदि भूपेश बघेल द्वारा किए गए इन ट्वीट्स का सही जवाब नहीं मिलता है, तो वह इसका जवाब मांगने उनके घर भी जाएंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ की साय सरकार की नीतियों और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार पोस्ट करते रहते है। हाल ही में उन्होंने डिप्टी सीएम अरुण साव और विधायक अजय चंद्राकर का वीडियो साझा कर छत्तीसगढ़ में शराब बंदी को लेकर तंज कस्ते हुए पोस्ट किया था, जिसके कैप्शन में उन्होंने स्कूल बंद स्कॉच शुरू लिखा है।

पूंजीपथरा पुलिस ने अवैध कबाड़ परिवहन में संलिप्त तीन ट्रकों से जब्त की 10.8 मीट्रिक टन स्क्रैप

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन पर जिले में अवैध कबाड़ के परिवहन और संग्रहण पर प्रभावी कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में थाना प्रभारी पूंजीपथरा, निरीक्षक राकेश मिश्रा के नेतृत्व में एक बार फिर अवैध कबाड़ पर कार्रवाई की गई है। दिनांक 15 नवंबर 2024 की शाम, पूंजीपथरा पुलिस ने क्षेत्र में वाहनों की सघन जांच के दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर ग्राम उज्जपुर अंजनी स्टील प्लांट के पास से तीन संदिग्ध ट्रकों को रोका।

वाहन जांच के दौरान ट्रकों में बड़ी मात्रा में लोहे का स्क्रैप, पुरानी साइकिलें और मोटर पार्ट्स पाए गए। जब वाहन चालकों से कबाड़ के परिवहन से संबंधित दस्तावेज मांगे गए, तो वे इसे प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। चोरी की संपत्ति होने के संदेह में पुलिस ने ट्रकों और उनमें लदे कुल 10.820 मीट्रिक टन स्क्रैप, जिसकी कीमत 3,88,485 रुपये आंकी गई है, जिसे जब्त कर लिया गया है।

पकड़े गए आरोपितों की जानकारी

1. लखंदर राम (35 वर्ष), निवासी खैरपुर, थाना कोतरारोड़, जिला रायगढ़। उसके ट्रक (क्रमांक CG13X1109) में 2.420 मीट्रिक टन स्क्रैप जिसकी कीमत 96,800 रुपये थी।

2. अजीत प्रजापति (28 वर्ष), निवासी बंजारी, थाना पाटन, जिला पलामू, झारखंड। उसके ट्रक (क्रमांक CG13AW0337) में 3.7 मीट्रिक टन स्क्रैप जिसकी कीमत 1,34,000 रुपये थी।

3. सुल्तान खान (57 वर्ष), निवासी आजाद मोहल्ला, थाना कुनकुरी, जिला जशपुर। उसके ट्रक (क्रमांक CG14D0528) में 5 मीट्रिक टन स्क्रैप जिसकी कीमत 1,57,685 रुपये थी।

थाना पूंजीपथरा में तीनों वाहन चालकों पर पृथक-पृथक धारा 35(क)(ड) BNSS/303(2) BNS के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है। निरीक्षक राकेश मिश्रा के नेतृत्व में इस कार्रवाई में एएसआई विजय एक्का, जयराम सिदार, प्रधान आरक्षक लाजरूस मिंज, विनीत तिर्की और हमराह स्टाफ ने सक्रिय भूमिका निभाई।

छत्तीसगढ़ में पिछले 11 महीनों में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवासों के निर्माण में आई तेजी : पिछले 11 माह में लगभग 50 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए सर्वेक्षण शुरू, नए हितग्राहियों को भी अब मिलेंगे आवास

रायपुर। आरएनएस

छत्तीसगढ़ में पिछले साल दिसम्बर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद से शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों में तेजी आई है। दिसम्बर-2023 से अक्टूबर-2024 के बीच पिछले 11 महीनों में ही करीब 50 हजार आवासों के निर्माण पूर्ण किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हर गरीब के लिए आशियाने के सपने को पूरा करने का काम छत्तीसगढ़ में तेजी से हो रहा है। दिसम्बर-2023 में राज्य में नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यों में तेजी लाते हुए 49 हजार 834 आवासों का काम पूर्ण किया गया है। इनमें विभिन्न शहरों के हितग्राहियों द्वारा अपनी खुद की जमीन पर बनाए गए 44 हजार 419 और योजना के साथ भागीदारी में किफायती आवासीय परियोजनाओं के माध्यम से निर्मित 5415 आवास शामिल हैं।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने बताया कि बीते 11 महीनों में योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति में अच्छी तेजी आई है। सभी नगरीय निकायों में बनाए जा रहे आवासों और निर्माण एजेंसियों के कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है और उन्हें गरीबों के आशियाने के सपने को जल्द पूरा करने के लिए तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 11 महीनों के दौरान हर माह औसतन हितग्राहियों द्वारा अपनी खुद की भूमि में बनाए जा रहे 4002 मकानों के काम पूर्ण किए गए हैं, जबकि वर्ष 2018 से 2023 के बीच यह औसत केवल 1592 थी। योजना के साथ भागीदारी में बनाए जा रहे किफायती आवासीय परियोजनाओं के निर्माण और आबंटन में भी तेजी लाते हुए विगत 11 महीनों में 7348 परिवारों को आवास आबंटित कर 5855 हितग्राहियों को पूर्ण आवासों में व्यवस्थापित किया गया है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए भी प्रदेश में सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत ऐसे शहरी पात्र परिवार जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में आवास नहीं मिल पाए थे, उन्हें पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में हितग्राहियों की सुविधा के लिए आवास हेतु आवेदन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। आवास के आवेदन सरलतापूर्वक ऑनलाईन माध्यम से भारत सरकार के अधिकृत पोर्टल पर स्वयं हितग्राही द्वारा दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रदेश की सभी 189 अधिसूचित नगरीय निकायों में हेल्पडेस्क के माध्यम से भी आवेदन की प्रक्रिया संपादित की जा सकती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में कुल दो लाख 49 हजार 166 आवास स्वीकृत हैं। इनमें लाभार्थियों द्वारा अपनी खुद की भूमि पर बनाए जाने वाले दो लाख 11 हजार 069 और किफायती आवासीय परियोजनाओं के तहत बनने वाले 38 हजार 097 आवास शामिल हैं। शहरी गरीबों के स्वयं के पक्के मकान का सपना जल्द से जल्द पूरा करने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा तेजी से इन आवासों का निर्माण किया जा रहा है। योजना के तहत राज्य में अब तक कुल एक लाख 96 हजार 967 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, जिनमें से एक लाख 74 हजार 967 आवास हितग्राहियों द्वारा बनाए गए हैं। वहीं किफायती आवासीय परियोजनाओं के तहत 21 हजार 600 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों में अभी कुल 48 हजार 346 आवासों का काम प्रगति पर है, जिन्हें तेजी से पूरा किया जा रहा है।

3 फरार वारंटियों को पुसौर पुलिस ने गिरफ्तार कर किया न्यायालय में पेश

रायगढ़

पुसौर पुलिस ने आज तीन फरार वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। ये वारंटी मारपीट मामले के आरोपी थे और न्यायालय में पेशी के लिए उपस्थित नहीं हुए थे, जिसके कारण माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़ के न्यायालय ने इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

गिरफ्तारी वारंट के परिपालन में पुसौर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के घर दबिश दी और उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में टीकम सिदार (46 वर्ष), अजय सिदार (23 वर्ष), और खीरसागर सिदार (28 वर्ष), सभी निवासी ग्राम जिलाड़ी थाना पुसौर शामिल हैं। गिरफ्तार वारंटियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत माननीय न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि वे न्यायालय की कार्यवाही के लिए समय पर उपस्थित हों और वारंट या कानूनी मामलों में सहयोग करें। न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकते हैं, जिससे आगे की कानूनी कार्रवाई होती है।

मध्यम वर्ग को संपत्ति रजिस्ट्री में बड़ी राहत : अब गाइड लाइन मूल्य पर ही लगेगा रजिस्ट्री शुल्क

- वास्तविक मूल्य पर मिल सकेगा बैंक लोन

रायपुर। आरएनएस

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के पहल पर छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति खरीदने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत दी है। अब किसी भी प्रापर्टी की खरीद-बिक्री में गाइड लाइन दर से सौदे की रकम अधिक होने पर भी रजिस्ट्री शुल्क गाइड लाइन दर के अनुसार ही लिया जाएगा। इससे बैंक लोन पर निर्भर मध्यम वर्गीय परिवार को वास्तविक मूल्य के आधार पर ऋण मिल सकेगा।

उल्लखेनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले से विशेषकर उन नागरिकों को लाभ होगा, जो बैंक ऋण के माध्यम से संपत्ति खरीदते हैं। पूर्व में संपत्ति की खरीद-बिक्री में गाइड लाइन दर और सौदे की राशि में जो भी अधिक होता था, उस पर रजिस्ट्री शुल्क देना आवश्यक था। उदाहरण के लिए यदि किसी संपत्ति का गाइड लाइन मूल्य 10 लाख रुपये है और उसका सौदा 15 लाख में हुआ, तो रजिस्ट्री शुल्क 15 लाख पर 4 प्रतिशत के हिसाब से 60 हजार रुपये देना पड़ता था।

इस नियम में संशोधन के बाद संपत्ति खरीदने वाले अब सौदे की रकम गाइड लाइन दर से अधिक होने पर भी वास्तविक मूल्य को अंकित कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें कोई रजिस्ट्री शुल्क नहीं देना होगा। 10 लाख रुपये की गाइड लाइन मूल्य वाली प्रॉपर्टी का सौदा 15 लाख में होता है, तो भी रजिस्ट्री शुल्क 10 लाख के 4 प्रतिशत के हिसाब से 40 हजार रुपये देय होगा। इस तरह 20 हजार रुपये की बचत होगी।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि इस संशोधन से मध्यम वर्गीय परिवारों को वास्तविक मूल्य के आधार पर अधिक बैंक ऋण प्राप्त करने में सहूलियत होगी। इसके अलावा यह निर्णय संपत्ति बाजार में पारदर्शिता व स्पष्टता को बढ़ाने में भी सहायक होगा और इससे वास्तविक मूल्य दर्शाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा।

देश के अन्य राज्यों में जमीन की गाइडलाइन कीमत या सौदा मूल्य दोनों में से जो ज्यादा हो उस पर पंजीयन शुल्क लगता है। केवल मध्य प्रदेश में गाइडलाइन कीमत से अधिक सौदा मूल्य दर्शाने पर उसमें पंजीयन शुल्क में छूट दी गई है। इसके कारण वहां लोगों में वास्तविक सौदा मूल्य को रजिस्ट्री पेपर में लिखने की प्रवृत्ति में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

वर्तमान में किसी संपत्ति का सौदा मूल्य सामान्यत: गाइडलाइन मूल्य से बहुत ज्यादा होता है। लेकिन लोग गाइडलाइन मूल्य या इसके आसपास का ही सौदा मूल्य अंकित करते हैं। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि अगर वास्तविक सौदा राशि अंकित कर देंगे, तो पंजीयन शुल्क गाइडलाइन मूल्य या वास्तविक सौदा राशि दोनों में से जो ज्यादा हो उस पर लगेगा। अधिक पंजीयन शुल्क से बचने के लिए लोग गाइडलाइन कीमत या इसके आसपास पूर्णांकित करते हुए सौदा मूल्य डाल देते हैं।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल का सीधा लाभ राज्य के सभी मध्यमवर्गीय परिवारों को मिलेगा क्योंकि अधिकांश मध्यमवर्गीय परिवार संपत्ति खरीदने के लिए बैंक लोन पर निर्भर रहते हैं। बैंक लोन रजिस्ट्री पेपर में दिखाए गए सौदे के रकम के आधार पर मिलता है, लोग पंजीयन शुल्क से बचने के लिए गाइडलाइन कीमत के बराबर सौदा मूल्य दिखाते हैं।कम सौदा कीमत दिखाएं जाने से बैंक लोन भी कम मिलता है।इस नीति से आमजनों को न्यायिक प्रकरणों में भी संपत्ति का वास्तविक मूल्य प्राप्त होगा। यदि कभी संपत्ति में कुछ धोखाधड़ी पायी गई तो व्यक्ति विक्रेता से वही मुआवजा पाने का हकदार होता है, जो रजिस्ट्री पेपर में लिखा हुआ। संपत्ति का सही मूल्य रजिस्ट्री में अंकित होने से प्रभावित व्यक्ति को उसका सही मुआवजा प्राप्त हो पायेगा।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480